

प्रेषक,

एम0एच0शासन

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक

24 मई, 2010

विषय:- अनुदान सं0-31 "टी0एस0पी0" के अन्तर्गत वन विभाग की आयोजनागत पक्ष की योजना हेतु वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग के पत्र सं0-1407/123/रा0यो0आ0/ प्लान/2010 दिनांक 29 अप्रैल, 2010, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-311/XVII/10-38(प्रकोष्ठ)/2008 दिनांक 07 मई, 2010 तथा आपके पत्र सं0-नि.1733/2-36(अ0जा0उपयोजना) दिनांक 22 अप्रैल, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग की आयोजनागत पक्ष में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत पिछौरागढ़ वन प्रभाग एवं भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी में संचालित "सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना" के लिए चालू वित्तीय वर्ष में रु0 62,50,000/- (रु0 बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण / व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किस्तों में किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनाएँ एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. योजना / परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग(त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
7. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
8. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेतर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।



10. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-०६/ख-२-२०१०-१२(११)/२००९ दिनांक ३१ मार्च, २०१० द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
11. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
12. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
14. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
15. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-२११(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
16. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की १० तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायित/बाह्य सहायित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
17. जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष होगा. भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो.
18. यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात् योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष २००९-१० में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.

२- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के लेखानुदान की अनुदान सं०-३१(टी०एस०पी०) के लेखाशीर्षक २४०६-वानिकी तथा वन्य जीवन ०१-वानिकी ७९६-जनजाति क्षेत्र उप योजना ०४-“सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना” की निम्नलिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि रु० हजार में)

क्र.सं.	मानक मद	बजट प्रावधान	वर्तमान स्वीकृति
१	२४-वृहत निर्माण	१००००	५०००
२	२९-अनुरक्षण	२५००	१२५०
	<b>योग</b>	<b>१२५००</b>	<b>६२५०</b>

(वर्तमान स्वीकृति रु० बासठ लाख पचास हजार मात्र)

३- उक्त आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भ पत्र संख्या-४२३/नि०स०/स्टा०अफ०-मु०स०/२०१० दिनांक ०७ मई, २०१० के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है.

भवदीय

(एम०एच०खान)

सचिव

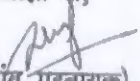
ब-१४५

संख्या- (१)/ख-२-२०१०, तददिनांकत.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहरनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
२. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-१/१०५, इन्दिरानगर, देहरादून.

3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
7. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
- ✓ 13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,  
  
(सुशान्त पटनायक)  
अपर सचिव